



महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग सात

वर्ष ३, अंक ३६]

बुधवार, नोवेंबर ८, २०१७/कार्तिक १७, शके १९३९

[पृष्ठे ४, किंमत : रुपये ४७.००

असाधारण क्रमांक ६०

प्राधिकृत प्रकाशन

अध्यादेश, विधेयके व अधिनियम यांचा हिंदी अनुवाद (देवनागरी लिपी)

विधि तथा न्याय विभाग

मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक,
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांकित ३० अक्टूबर २०१७।

MAHARASHTRA ORDINANCE No. XXIV OF 2017.

AN ORDINANCE

FURTHER TO AMEND THE PANDHARPUR TEMPLES ACT, 1973.

महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक २४ सन् २०१७।

पंढरपुर मंदिर अधिनियम, १९७३ में अधिकतर संशोधन संबंधी अध्यादेश।

क्योंकि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा है ;

और क्योंकि महाराष्ट्र के राज्यपाल का समाधान हो चुका है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं जिनके सन् १९७४ कारण उन्हें इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, पंढरपुर मंदिर अधिनियम, १९७३ में अधिकतर संशोधन करने के का १। लिए सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ है ;

अब, इसलिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद २१३ के खण्ड (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महाराष्ट्र के राज्यपाल, एतद्वारा, निम्न अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं, अर्थात् :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भण ।

सन् १९७४ का महा. ९ की धारा २ में संशोधन।

सन् १९७४ का महा. ९ की धारा २१ में संशोधन।

सन् १९७४ का महा. ९ की धारा २४ में संशोधन।

सन् १९७४ का महा. अध्या. क्र. २४।

सन् १९७४ का महा. ९ की धारा २५ में का प्रतिस्थापन।

सन् १९७४ का महा. ९ की धारा २९ में संशोधन।

सन् १९७४ का महा. ९ की धारा ३० में संशोधन।

१. (१) यह अध्यादेश पंढरपुर मंदिर (संशोधन) अध्यादेश, २०१७ कहलाए।

२. पंढरपुर मंदिर अधिनियम, १९७३ (जिसे इसमें आगे, “मूल अधिनियम” कहा गया है) की धारा सन् १९७४ का महा.

१।

“(ध) “सदस्य” का तात्पर्य, समिति के सदस्य से है और इसमें धारा २१ की उप-धारा (१) के खण्ड (क) के अधीन नियुक्त अध्यक्ष और सह-अध्यक्ष सम्मिलित होंगे ; ”।

३. मूल अधिनियम की धारा २१, की उप-धारा (१) के,—

(क) खण्ड (क) में, “अध्यक्ष सम्मिलित होगा” शब्दों के स्थान में, “अध्यक्ष और सह-अध्यक्ष सम्मिलित होगा” शब्द रखे जायेंगे ;

(ख) खण्ड (क) के स्थान में, निम्न परन्तुक, जोड़ा जायेगा, अर्थात् :—

“परन्तु, सह-अध्यक्ष जैसा की विहित किया जाए, अध्यक्ष के ऐसे कार्यों का अनुपालन और ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेगा ; ”।

४. मूल अधिनियम की धारा २४ के परन्तुक के पश्चात्, निम्न परन्तुक, जोड़ा जायेगा, अर्थात् :—

“परन्तु आगे यह कि, पंढरपुर मंदिर (संशोधन) अध्यादेश, २०१७ के प्रारम्भण के पश्चात्, नियुक्त प्रथम सह-अध्यक्ष का पदावधि नियुक्त किये गये समिति सदस्यों की पदावधि से सह-पर्यवसित होगी, देखिए सरकारी अधिसूचना, विधि तथा न्याय विभाग, क्रमांक पीटीए. २०१४/सी.आर. ०७/डी-१६, दिनांकित ३

”।

५. मूल अधिनियम की धारा २५ के स्थान में, निम्न धारा, रखी जायेगी, अर्थात् :—

“२५. (१) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कोई सदस्य, अध्यक्ष को अपने स्वहस्ताक्षरित पते द्वारा अध्यक्ष को अपने पद का त्याग कर सकेगा।

(२) सह-अध्यक्ष और अध्यक्ष, राज्य सरकार को उसी प्रकार की सूचना द्वारा अपने पद का त्याग कर सकेंगे।

(३) सूचना विहित रीत्या में परिदृष्ट की जायेगी।

(४) सदस्य का पद, अध्यक्ष द्वारा त्यागपत्र की स्वीकृति के दिनांक से रिक्त होगा और सह-अध्यक्ष या, यथास्थिति, अध्यक्ष का पद राज्य सरकार द्वारा त्यागपत्र स्वीकृति के दिनांक से रिक्त होगा। ”।

६. मूल अधिनियम की धारा २९, की उप-धारा (१) में, “अध्यक्ष या सदस्य” शब्दों के स्थान में, “अध्यक्ष, सह-अध्यक्ष या सदस्य” शब्द रखे जायेंगे।

७. मूल अधिनियम की धारा ३० की, उप-धारा (५) के स्थान में, निम्न उप-धारा, रखी जायेगी, अर्थात् :—

(५) समिति की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता, अध्यक्ष द्वारा की जायेगी और उसकी अनुपस्थिति में सह-अध्यक्ष द्वारा की जायेगी, और अध्यक्ष तथा सह-अध्यक्ष दोनों की अनुपस्थिति में उस अवसर के लिए अध्यक्षता के लिए उपस्थित सदस्यों में से चयनित सदस्य द्वारा की जायेगी। ”।

८. मूल अधिनियम की धारा ३१ में, “ अध्यक्ष या ” शब्द, दोनों स्थानों पर जहाँ कहीं वे आये हों, के सन् १९७४ का महा. ९ की स्थान में “ अध्यक्ष, सह-अध्यक्ष या ” शब्द रखे जायेंगे।
धारा ३१ में संशोधन।

सन् १९७४ ९. (१) पंढरपुर मंदिर अधिनियम, १९७३ के उपबंधों को प्रभावी करने में यदि कोई कठिनाई उद्भूत कठिनाई के का महा. होती है तो इस अध्यादेश द्वारा, यथा संशोधित, राज्य सरकार राजपत्र निराकरण की शक्ति।
१। उद्भूत हो, उक्त अधिनियम के उपबंधों से अन्-असंगत कोई बात कर सकेगी, जैसा अवसर शक्ति। उक्त अधिनियम के उपबंधों से अन्-असंगत कोई बात कर सकेगी, जैसा अवसर शक्ति।

(२) उप-धारा (१) के अधीन बनाया गया प्रत्येक आदेश, उसके बनाए जाने के बाद, यथा संभव शीघ्र, राज्य विधान मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष के रखा जायेगा।

वक्तव्य।

पंढरपुर मंदिर अधिनियम, १९७३ (सन् १९७४ का महा. ९) अन्य बातों के साथ-साथ पंढरपुर में विडुल और रुक्मिणी के मंदिर में कार्यरत सेवक और पुरोहिती प्रवर्गों के सभी वंशागत अधिकारों, विशेषाधिकारों के उत्सादन के साथ ही ऐसे अधिकारों और विशेषाधिकारों के अर्जन के लिये और प्रयोजन के लिये स्थापित समिति में ऐसे अधिकारों और विशेषाधिकारों को निहित करने के लिये और उन मंदिरों के बेहतर प्रशासन और सुशासन के लिये उपबंध करता है।

इन मंदिरों में, चैत्री, आषाढ़ी, कार्तिकी और माघी यात्राओं के संबंध में धार्मिक कृत्य और धर्मानुष्ठान परंपरागत रीति से संपन्न होते हैं।

२. उक्त अधिनियम की धारा २१, राज्य सरकार को, राज्य में साधारण रूप से रहनेवाले व्यक्तियों में से, जो भगवान विडुल और देवी रुक्मिणी के भक्त हैं और जो उनकी नियुक्ति के पूर्व, इस प्रयोजन के लिये राज्य सरकार द्वारा अभिनिर्धारित प्ररूप में तदनुसार, अभिघोषणा करता है, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये जाने वाले अध्यक्ष समेत ग्यारह सदस्यों से सम्मिलित समिति स्थापित करने की शक्ति प्रदान करती हैं और पंढरपुर नगर परिषद का अध्यक्ष, पदेन सदस्य होगा।

३. समिति के कार्यों के अधिक समन्वयन और कार्यक्षम प्रबंधन के उद्देश्य को प्राप्त करने के उद्देश से और परंपराओं और रिवाजों के अनुपालन के साथ धार्मिक कृत्य और धर्मानुष्ठान संपन्न किये जाते हैं और धार्मिक भावनाओं को सम्यक महत्व दिया जाता है कि सुनिश्चित करने की दृष्टि से समिति के सह-अध्यक्ष की नियुक्ति करने के लिये उपबंध करना इष्टकर समझा गया है, जो, नियमों द्वारा विहित किया जाए अध्यक्ष के ऐसे कृत्यों का अनुपालन करेगा और ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। अतः इसलिये, उक्त अधिनियम में यथोचित संशोधित करना इष्टकर है।

४. ३१ अक्टूबर, २०१७ को होनेवाली आगामी कार्तिकी यात्रा को ध्यान में रखते हुये, इस निमित्त संशोधनों का कार्यन्वयन करना इष्टकर समझा गया है।

५. क्योंकि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा है और महाराष्ट्र के राज्यपाल का समाधान हो चुका है कि, ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं, जिसके कारण उन्हें, उपरोक्त प्रयोजनों के लिये, पंढरपुर मंदिर अधिनियम, १९७३ (सन् १९७४ का महा. ९) में अधिकतर संशोधन करने के लिये सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ है, अतः यह अध्यादेश प्रख्यापित किया जाता है।

मुंबई,

दिनांकित २८ अक्टूबर २०१७।

चे. विद्यासागर राव,

महाराष्ट्र के राज्यपाल।

महाराष्ट्र के राज्यपाल के आदेश तथा नाम से,

बि. ज. जमादार,
सरकार के प्रधान सचिव और विधि परामर्शी।

(यथार्थ अनुवाद),

हर्षवर्धन जाधव,
भाषा संचालक, महाराष्ट्र राज्य।